

## बिहार विशेष करंट अफेयर्स अप्रैल 2021

### बिहार राज्य पर टीकाकरण का सबसे अधिक बोझ

- इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च (Ind-Ra) के अनुसार भारत को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए 67,193 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो देश की कुल जीडीपी का 0.36% है।
- भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के 84.19 करोड़ लोग हैं जो नए नियमों के तहत टीकाकरण के लिए पात्र हैं।
- इसमें केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए कुल 20,870 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.12% है, जबकि राज्य सरकारें 46,323 करोड़ रुपये खर्च करेंगी जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.24% है।
- राज्यों में टीकाकरण का सबसे अधिक बोझ बिहार सरकार पर पड़ेगा, जो कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.6% खर्च करेगी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 0.47% और झारखंड में जीएसडीपी का 0.37% होगा।

### इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च:

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) एक निजी फर्म है जो भारत के क्रेडिट बाजारों और संभावित क्रेडिट विचारों पर रिपोर्ट प्रदान करती है।

वर्तमान में Ind-Ra कॉर्पोरेट मामलों, वित्तीय संस्थानों (बैंकों और बीमा कंपनियों सहित), वित्त और पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रबंधित फंड, शहरी स्थानीय निकायों और संरचित वित्त और परियोजना वित्त कंपनियों के कवरेज को बनाए रखने का काम करता है।

### मेवालाल चौधरी (बिहार में पूर्व शिक्षा मंत्री) का निधन

- बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक मेवालाल चौधरी का COVID-19 के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 4 जनवरी 1953 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था।
- वे 68 वर्ष के थे और उनका इलाज पटना, बिहार में चल रहा था।

- वह जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी से जुड़े थे और तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। कॉलेज शिक्षकों की भर्ती के विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में उनका नाम आने पर उन्हें राज्य के शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था।

### राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक संयुक्त फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए भारत में अनुकूल नियोजन के लिए "राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन" रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार और भारत के अन्य पूर्वी राज्य "जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक भेद्यता" की श्रेणी में आ गए हैं।
- बिहार के अलावा अन्य 7 राज्य हैं: मिजोरम, ओडिशा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश।
- बिहार, झारखंड, और असम के 60% से अधिक जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में हैं।
- रिपोर्ट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, स्विस् एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। रिपोर्ट को डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने जारी किया।

### हरित ऊर्जा कुशल दो शहरों के साथ बिहार बना भारत का पहला राज्य

- बिहार राज्य के दो शहरों, राजगीर और बोधगया को 2023 से अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के जरिए सौर ऊर्जा मिलेगी। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसमें हरित ऊर्जा कुशल 2 शहर शामिल होंगे।
- आवश्यक हरित ऊर्जा आपूर्ति सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी।
- राज्य सरकार परियोजना को लागू करने के लिए लखीसराय और भागलपुर में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगी।
- कार्यक्रम के तहत, राजगीर और बोधगया के दो शहरों के हरित ऊर्जा कुशल होने के बाद, गवर्नर हाउस, उच्च न्यायालय आदि जैसे सरकारी कार्यालय भी ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा पर चलेंगे।

## सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रण में है।
- SECI की स्थापना 2011 में की गई थी।
- मूल रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित CPSU के आदेश को पूरे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को कवर करके आगे बढ़ाना है।

Gradeup